दिनांक-26 नवम्बर, समय : 1:15 pm

**मुख्य परीक्षा**

**प्रश्न-** **राजनीतिक हिंसा, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन आदि कारणों से सरकार द्वारा 'इंटरनेट शटडाउन' यानी इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाना कहाँ तक उचित है? परीक्षण कीजिए। ( 150 शब्द )**

**How much relavant is the 'Internet Shutdown' or censoring Internet Services by the government due to political violence, protests and movements. Examine. (150 Words)**

**मॉडल उत्तर**

**दृष्टिकोण:**

- भूमिका में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका के संदर्भ में चर्चा करें।
- पैराग्राफ बदलकर इंटरनेट की सुविधा का अधिकार एक उत्तम पहल क्यों? इसके बारे में बताएं।
- फिर पैराग्राफ बदलकर इंटरनेट शटडाउन अनुचित क्यों? स्पष्ट करें।
- अंत में संक्षिप्त व संतुलित निष्कर्ष दें।

**उत्तर-** विदित हो कि उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाने के राज्यों के अधिकारों को चुनौती देने वाली वर्ष 2016 में दायर एक अपील खारिज कर दी थी। न्यायालय का मानना था कि कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इस तरह का प्रतिबंध लगाना गलत नहीं है।

**इंटरनेट की सुविधा का अधिकार एक उत्तम पहल क्यों?**

- आज जब सरकार कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के अभियान के साथ ही ई-गवर्नेंस और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में इंटरनेट तक सबकी पहुंच ज्यादा जरूरी हो जाती है। विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र ने भी यह कहा है कि विश्व के सभी देशों को इंटरनेट की सुविधा को बुनियादी मानवाधिकार घोषित कर देना चाहिए। विश्व के कई देश पहले ही व्यवस्था को अपना चुके हैं।

**इंटरनेट शटडाउन अनुचित क्यों?**

- यदि जाट या पाटीदार आंदोलन हो या फिर बाबा राम रहीम का मामला, इनमें इंटरनेट बंद नहीं किया गया। यदि बंद किया जाता तो शायद हिंसा और भी विकराल हो सकती थी।
- धार्मिक समूहों में टकराव की संभावना को टालने के लिए भी ऐसा करना सही लगता है।
- ऐसी खतरनाक और अप्रिय स्थितियों को टालने के लिए आर्थिक नुकसान को नजरअंदाज कर देना भी गलत नहीं कहा जा सकता है।
- आज इंटरनेट हम सबके जीवन का अहम हिस्सा है। यहां तक कि सरकार भी अपने कई काम इंटरनेट के जरिए करती है। जाहिर है कि इंटरनेट अब हवा-पानी की तरह ही हो चुका है। यदि प्रशासन हिंसक स्थिति में पानी की सप्लाई नहीं बंद करता तो फिर इंटरनेट बंद करना कहां तक उचित है?